भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4410

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

तमिलनाडु में पथ विक्रेता

4410. श्री जी. सेल्वमः

श्री सी. एन. अन् नादुरईः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आरंभ से लेकर अब तक कितने पथ विक्रेता लाभान्वित हुए हैं;

(ख) तमिलनाडु में उक्त योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को स्वीकृत प्रथम, द्वितीय और तृतीय ऋणों की संख्या कितनी है साथ ही संवितरित की गई कुल राशि कितनी है;

(ग) तमिलनाडु में कितने पथ विक्रेताओं ने अपना पहला ऋण पूरी तरह से चुका दिया है और उक्त योजना के अंतर्गत दूसरा ऋण प्राप्त किया है;

(घ) क्या राज्य में सभी पात्र पथ विक्रेताओं को उक्त योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है और उन्हें पहचान पत्र प्रदान किए गए हैं;

(ङ) तमिलनाडु में कितने पथ विक्रेताओं ने उक्त योजना के अंतर्गत डिजिटल भुगतान तंत्र को अपनाया है,

(च) तमिलनाडु में उक्त योजना के अंतर्गत विक्रेताओं को प्रदान की गई ब्याज राजसहायता की कुल राशि कितनी है; और

(छ) क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं के बीच अधिक डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

क. योजना की शुरुआत से 20.03.2025 तक, प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में कुल 3,99,930 पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया गया है।

ख. 20.03.2025 तक, तमिलनाडु राज्य में पीएम स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं को पहले, दूसरे और तीसरे स्वीकृत ऋण और संवितरण का विवरण;

ऋण अवधि	ऋण आवेदन स्वीकृत	ऋण आवेदन संवितरित	धनराशि संवितरित (₹ करोड़ में)
पहला ऋण	4,04,290	3,99,930	397.5
दूसरा ऋण	1,43,752	1,38,370	276.01
तीसरा ऋण	28,947	27,269	134.61
कुल	5,76,989	5,65,569	808.12

ग. 19.03.2025 तक, तमिलनाडु राज्य में कुल 2,40,401 पथ विक्रेताओं ने सफलतापूर्वक अपना पहला ऋण चुका दिया है, जिनमें से 1,38,370 पथ विक्रेताओं ने दूसरा ऋण लिया है।

घ. पथ विक्रेताओं की पहचान के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है तथा पहचान किए गए पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र भी प्रदान किए गए हैं।

ङ. 31.01.2025 तक, अब तक 2.49 लाख डिजिटल रूप से सक्रिय पथ विक्रेताओं ने 26,941.92 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 20.71 करोड़ डिजिटल लेनदेन किए हैं।

च. अब तक, इस योजना के तहत तमिलनाडु राज्य में पथ विक्रेता लाभार्थियों को 16.94 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी का भुगतान किया जा चुका है।

छ. सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को डिजिटल रूप से जोड़ने और प्रशिक्षण देने के लिए 4 जनवरी से 15 फरवरी, 2021 तक एक विशेष अभियान "मैं भी डिजिटल" चलाया गया था। डिजिटल लेनदेन को नए सिरे से बढ़ावा देने के लिए, 1 जुलाई से 15 अगस्त, 2021 तक "मैं भी डिजिटल 2.0" चलाया गया था। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को डिजिटल रूप से जोड़ने और प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआई) के साथ साझेदारी की है। इस पहल को और बढ़ाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संयुक्त रूप से 09 सितंबर से 30 नवंबर, 2021 तक पायलट आधार पर "मैं भी डिजिटल 3.0" शुरू किया है, जिसके तहत 223 चयनित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को डिजिटल रूप से शामिल करने और प्रशिक्षित करने के लिए 5 डीपीए (पेटीएम, फोनपे, भारतपे , एसवेयर ,

एमस्वाइप) को कार्य सौंपा गया था। "मैं भी डिजिटल 4.0"- डिजिटल ऑन-बोर्डिंग में तेजी लाने के लिए, 06 फरवरी, 2023 से हर महीने के पहले सोमवार से एक सप्ताह तक चलने वाले अभियान के साथ-साथ स्वनिधि से समृद्धि-शहर स्तरीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जनवरी, 2025 तक लगभग 67% लाभार्थी डिजिटल रूप से सक्रिय हैं।

*****